कृषि में कौशल विकास

डॉ. शक्ति जैन
प्राध्यापक-अर्थशास्त्र
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश -

भारत देश युवाओं का देश है वर्तमान समय ज्ञान व कौशल का है। भारत देश एक कृषि प्रधान देश अतः कृषि में कौशल विकास की आवश्यकता है। ग्रामीणों व युवा किसान पलायन ना करें कृषि छोड़कर मजदूर वने इसके लिए किसानों की आय में वृद्धि कृषि में कौशल व नई तकनीक तथा कृषि के साथ अन्य व्यवसाय की जा सकती है। सरकार द्वारा भी कृषि में कौशल विकास की कई योजनाएं वनाई जा रही है।

मुख्य शब्द - : समेकित कृषि, जनसांख्यिकीय संरचना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, खाद्य प्रसंस्करण।

भारत देश वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ता उसकी अनुकूल जनसांख्यिकीय संरचना है। 135 करोड़ जनसंख्या वाले भारत देश में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहां कामकाजी युवा वर्ग 15 वर्ष से 64 वर्ष के बीच की जनसंख्या 87.70 करोड़ है जो कि देश के में महत्वपूर्ण स्थान रखती है तथा लगभग 60.5 करोड़ जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु के हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के अनुसार यदि जनसांख्यिकीय लाभों का समुचित उपयोग किया जाए तो भारत अपनी सालाना विकास दर में तक का सुधार कर सकता है। 135 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत देश में 70.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में है तथा लगभग 60: जनसंख्या कृषि व कृषि से जुड़े व्यवसाय में लगी है जिनमें लगभग 35 करोड़ युवा ग्रामीण से हैं अतः आवश्यक है कि युवा वर्ग जो गांव से वड़ी मात्रा में पलायन कर रहा है उसको किस तरह कृषि व उससे सम्बंधित व्यवसाय में रोका जाए। क्योंकि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि महत्वपूर्ण स्थान रखती है कृषि विकास एक गुणक की तरह कार्य करता है कृषि से कृषकों की आय में होती है तो औद्योगिक वस्तु की मांग बढ़ती है जब औद्योगिक वस्तु की मांग बढ़ती है तो औद्योगिक वस्तु का बढ़ता है जिससे संपूर्ण बाजार का विस्तार होता है और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है।

कृषि क्षेत्र में कार्यरत युवाओं के समक्ष कृषि को लाभकारी बनाने में बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी है। वर्ग जो कौशल विकास के द्वारा कृषि कार्य को कर रहा है और भी कई तरह के कौशल विकास को अपनाकर हो सकता है। कृषि कार्य में कौशल विकास की कई संभावनाएं हैं।

कृषि में कौशल विकास की संभावनाएं -

कृषि में आय वृद्धि हेतु नए उद्यमों व नई नई तकनीक से विकास - सीमांत व छोटे किसान वर्तमान

नई तकनीक के साथ तालमेल नहीं कर पा रहे हैं अतः इन किसानों की आय बढ़ाने हेतु कौशल विकास से ही संभव है इसके लिए (1) किसानों को अपनी उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग कार्य, प्रसंस्करण कार्य आदि से अपनी आय बढ़ा सकते हैं। (2) किसानों का अपने उत्पादों का सीधा वितरण करना, अपने उत्पाद की अच्छी कीमत कहां मिलेगी वहां पर उपज को स्वयं ही भेज कर व्यवस्था करना। (3) किसानों को संगठित होकर एक ही तरह कि फल, फूल व सब्जियों की खेती इस तरह से करना कि वह क्षेत्र ही उन चीजों के लिए प्रसिद्ध हो जाए। ई-पोर्टल पर अपनी उपज व क्षेत्र का नाम अंकित करवाएं व एक सा उत्पाद होने पर इकट्ठे उपज भेजने पर परिवहन व्यय बचा कर भी आय में वृद्धि कर सकते हैं। (4) किसी एक उत्पाद पर केंद्रित रहने से उससे संबंधित ज्ञान अर्जन कर, कुशलता हासिल कर बाजार में अपनी अच्छी पकड़ बिठाकर अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। (5) समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर भी किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकता है एक विशेष उत्पाद के अतिरिक्त किसान अन्य कृषि उत्पाद भी यदि साथ में करें तो आय में भी वृद्धि होगी एवं जोखिम प्रवंधन भी होगा फसल प्रणाली की सघनता या प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाकर भी आय में वृद्धि हो सकती है।

कृषि विकास के लिए नई तकनीक व भारतीय कृषि से जुड़े व्यवसाय -

कृषि पर निर्भरता कम होना या प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में जाना एक देश के विकास की सूचक है। परंतु कृषि ही छोड़ देना गांव छोड़कर शहरों में रहना यह तो भारत देश के लिए समस्या है अतः आवश्यक है कि कृषि से संबंधित विषयों का आधुनिकीकरण करना। वर्तमान में गांव का युवा परंपरागत तरीके से कृषि नहीं कर सकता वह केवल कृषि पर निर्भर नहीं रह सकता इसलिए गांव के युवा वर्ग को कृषि व कृषि से जुड़े उद्योग धंधों को नई-नई तकनीक अपनाना चाहिए। उद्योग धंधे जो कृषि से जुड़े हैं जैसे -

(1) फलों और सब्जियों पर आधारित व्यवसाय -

फल और सब्जियों का सही संरक्षण एवं वैज्ञानिक प्रसंस्करण करके उसे राष्ट्रीय एवं विदेशी बाजारों में बेचकर ग्रामीण युवक घर पर ही अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि सीजन में फल और सब्जियां बहुत मात्रा में आती है उचित भंडारण, प्रसंस्करण के अभाव में नष्ट हो जाती है अतः उस समय उनका संरक्षण कर लाभ कमाया जा सकता है। सब्जियों में जैसे ब्रोकली, चाइनीज पत्ता गोभी बंद गोभी, विभिन्न रंगों वाली शिमला मिर्च आदि प्रचलित सब्जियों के अलावा कुछ ऐसी सब्जियां व फलों की जिनकी बाजार में अधिक मांग है, अधिक मूल्य मिलता है उन्हें उगाकर घरेलू बाजार के अतिरिक्त विदेशी बाजार में भी भेजा जा सकता है।

(2) वन और औषधियों का रोजगार -

वन औषधियों का निर्माण वर्तमान समय की मांग है आयुर्वेदिक औषधियों की वर्तमान में बहुत अधिक मांग है। चीन जैसा राष्ट्र वन औषधियों को भेजकर अग्रणी निर्यातक देश बन गया है जबकि भारत में औषधीय पौधों की सर्वाधिक विविधता है अतः इन वन औषधियों का उत्पादन बढ़ाकर आय व रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है। देश में बहुत सी आयुर्वेदिक संस्थान डाबर, हिमालय, झंडू, वैद्यनाथ आदि औषधीय पौधों को खरीदने के लिए तत्पर हैं औषधीय पौधों में सफेद मूसली, अश्वगंधा, तुलसी, ईसबगोल, सदाबहार, घृतकुमारी, सतावर, कुनैन, बच आदि का उत्पाद कर युवा अपने आय में वृद्धि कर सकता है। आज औषधि का उत्पाद कर उससे संबंधित प्रोडक्ट

बनाकर बाबा रामदेव करोड़ों रुपयों का टर्नओवर प्राप्त कर रहा है जो प्रत्येक भारतीय युवा के लिए एक उदाहर है। इन वन औषधि पौधों को लगाकर यह वर्ग आय व रोजगार प्राप्त कर सकता है।

(3) बागवानी फसलों की खेती -

बागवानी फसलों की खेती परंपरागत कृषि उत्पादन प्रणाली के स्थान पर युवा वर्ग के लिए एक अ विकल्प उपलब्ध है। सुरक्षित दशाओं में फसल उत्पादन से मुख्य तथा बेमौसम में सब्जियां, फूलों तथा फल आदि फल का उत्पादन कर उसमें गुणवत्ता बढ़ाकर वह सफलता प्राप्त हो सकती है और हो भी रही है जैसे टमाटर, चेरी टमा रंगीन शिमला मिर्च, अनिषेक जनन खिला, फूलों में गुलाव, रजनीगंधा ओमा वेला, बोनसाई सजावटी पौधे आदि क में स्ट्रावेरी, अंगूर आदि व्यवसाय उत्पाद काफी लाभप्रद हैं इस संबंध में कई सरकारी संस्थान कृषि विश्वविद्यालय आई आईएचआर बेंगलुरु, नई दिल्ली आदि से अच्छी प्रजातियों का बीज पौध प्राप्त कर नर्सरी बनाने का धंधा सभी ग्रामीण युवा के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है।

(4) बीज उत्पादन का व्यवसाय -

बीज खेती-बाड़ी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में कृषि उत्पादन को बढ़ा देने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम की स्थापना की जिसका उद्देश्य फसलों के प्रमाणित की के उत्पादन एवं वितरण में सुधार करना था। यदि ग्रामीण युवा जमीन को लीज पर लेकर यदि सामूहिक बीज बना बीज निर्माण का कार्य करें तो शुद्ध एवं उपयुक्त प्रजातियों का बीज किसानों को उपलब्ध हो जाएगा तथा ग्रामीण युवा को आकर्षक रोजगार एवं आय दोनों का लाभ प्राप्त होगा।

(5) जैविक खाद का निर्माण -

वर्तमान में जैविक खेती का महत्व बढ़ा है। रासायनिक खादों व उर्वरक का स्वास्थ्य पर पर्यावरण पर प्रभाव देखते हुए जैविक खाद से बनी वस्तुएं उत्पाद की अच्छी कीमत प्राप्त हो रही है। अतः गांव में युवा वर्ग किसान जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट, रासायनिक कीटनाशक दवाओं के स्थान पर जैव कीटनाशक जैसे नीम व गौमू आदि का उपयोग कर बना सकते हैं। जो कि आय का अच्छा स्त्रोत बन कर सामने आ रहा है।

(6) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग -

यह उद्योग किसानों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। भारतीय फूड प्रोसेसिंग सेक्टर दुनिया में आ नंबर पर हैं तथा देश के उद्योगों में पांचवें स्थान पर है तथा राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) मैं इसका हि 6.3 प्रतिशत है। कुल औद्योगिक उत्पाद में इसका हिस्सा 19% और निर्यात में 13% है। अभी इस उद्योग की बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। इस उद्योग से देश में औद्योगिक विकास ही नहीं बल्कि आय के समान वितरण सामाजिक समरसता के लिए भी आवश्यक है क्योंकि फूड प्रोसेसिंग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला का किसान व देश की कृषि है। एक अनुमान के अनुसार भारतीय किसान 1 वर्ष में फूड प्रोसेसिंग के लिए 45 व टन कच्चा माल तैयार करता है परंतु किसानों को इसका अधिकांश हिस्सा बिना प्रोसेसिंग के खुले बाजार में ही बे पड़ता है जिसका प्रभाव सीधा कीमत पर पड़ता है। किसान को जितना मूल्य मिल सकता है उतना नहीं मिलत अतः यह उद्योग किसान की आय को बढ़ा सकता है भारत सरकार ने कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में कौशल वि

ISSN 2395-051X

हेतु कई योजनाएं आरंभ की है जो कौशल विकास के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को जन्म देती है जिनमें से कुछ योजनाएं निम्न है -

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना -

यह भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य युवाओं में कौशल को बढ़ाना है। संपूर्ण देश में चल रही इस योजना का नियोजन का आंकड़ा 54.9% का है। इसमें नियोजन क्षमता बढ़ाने तथा बेरोजगारी और अल्प रोजगारी घटाने के अलावा उत्पादकता और आय में वृद्धि में लाने की भी क्षमता है यह योजना मुद्रा (माइक्रोयूनिट्स डेवलपमेंट एण्ड रिफाइनेंस एजेंसी) और स्टार्ट अप इंडिया के जरिए स्वरोजगार अभियान में भी सहायक है।

सन 2015 में स्वीकृत की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के कौशल प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण योजना है इसके तहत पाठयक्रमों में सुधार, वेतन शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। नवगठित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ;छैक्द्ध के माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है अभी इस योजना के तहत एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित होगा। इसमे निम्न योजनायें शामिल हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना -

भारत सरकार ने वर्ष 2008 में इस योजना की शुरूआत की थी। इसके कार्यान्वयन हेतु राज्य कृषि विभाग नोडल विभाग रहेगा। मुख्य फसलों जैसे गेहूं, दान को मोटे अनाज, छोटे अनाज, दलहन तथा तिलहन का समेकित विकास, किसानों को प्रमाणित वीजों की उपलब्धता, प्रजनक वीजों के उत्पादन, आईसीएआर सार्वजनिक क्षेत्र बीज निगमों से प्रजनक वीजों की खरीद, प्रमाणित बीजों का उत्पादन, बीज उपचार, प्रदर्शन स्थलों पर किसान फील्ड स्कूल, किसानों को प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त कृषि मशीनीकरण मृदा स्वास्थ्य की वृद्धि के संबंध में गतिविधियां गरीबी रेखा क्षेत्रों में से नीचे के किसानों को आजीविका प्रदान करने के लिए समेकित कृषि प्रणाली, समेकित कीट प्रबंधन योजनाएं, बागवानी उत्पादन की वृद्धि से संबंधित गतिविधियां, पशुपालन आदि विकास गतिविधियों में सहायता प्रदान की जा सकती है।

भारतीय कृषि कौशल परिषद -

इसकी स्थापना वर्ष 2013 में कृषि तथा कृषि से संबंधित क्षेत्रों में कौशल एवं उद्यमिता विकास हेतु किया गया। इसका कार्य देशभर में कृषि में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दे रहा है। देश में कृषि के साथ पशुपालन, बागवानी, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन वानिकी, रेशम कीट पालन, कुक्कुट पालन जैसे कृषि संबंधित क्षेत्रों में भारतीय कृषि कौशल परिषद किसानों का कौशल विकास कर रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद -

इस परिषद ने किसानों को उन्नत तकनीकों, नई उत्पादन प्रौद्योगिकी की उन्नत किस्में ऋण और लिंकेज सुविधाओं में अनुसंधान शिक्षण एवं प्रसार के साथ कृषि में कौशल विकास व स्वरोजगार हेतु नए कदम उठाए गए

हैं जैसे कृषि में मूल्य संवर्धन और प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केंद्र (वाटिका), मेरा गांव मेरा गौरव, फार्मर फर्स्ट, कृ युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना (आर्या), ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना (य रेडी), कृषि विज्ञान केंद्रों में कौशल विकास आदि।

भारत देश युवाओं का देश है भारत में कौशल विकास के लिए सरकार प्रयत्नशील है 2022 तक 40 क नागरिकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। तथा भारत सरकार भी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी क की पहल एक महत्वपूर्ण एवं उपयुक्त कदम है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कौशल विकास कार्य तकनीकी तथा सरकार की नीतियों का कुशल समन्वय कर कृषि क्षेत्र में कौशल विकास निश्चित ही अधिक अधिक करना ही होगा। विकास से गांव का विकास, कृषि गांव के विकास से देश का विकास है। प्रधानमंत्री न जी ने लघु उद्योगों के संबंध में एक बात कही की दो बातों में कंप्रोमाइज ना करें जीरो डिफेक्ट एवं जीरो इफे (जेड) हम यह बनाएं जिसमें जीरो डिफेक्ट होता कि दुनिया के बाजारों में कभी वापस ना आए तथा हम मैन्युफैक्च करें जिसमें जीरो इफेक्ट हो अर्थात पर्यावरण पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। वर्तमान समय ज्ञान व अनु कौशल का युग है वर्तमान कृषि भी कौशल मांग रही है पारंपरिक ज्ञान बेहतर प्रौद्योगिकी दोनों ही के प्रयोग से कृ का विकास संभव है शिक्षित युवा वर्ग कृषि को नई-नई ज्ञान व कौशल से सजा कर देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइ पर पहुंचा सकता है।

संदर्भ -

1. डॉ. आर. के. गोविल, कृषि अर्थशास्त्र, एल.एन, अग्रवाल प्रकाशन, 2013-14
2. डॉ. मामोरिया एवं डॉ. जैन, भारतीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, 2010
3. कुरूक्षेत्र पत्रिका, मार्च 2019, जुलाई 2019
4. योजना, मार्च 2016
5. दैनिक भास्कर, मार्च 2019
6. kisansamadhan.com
7. www.livehindustan.com